

भ्रष्टाचार और फासी शक्तियों के विरुद्ध शंखनाद

नवयुग

R.N.I. No. 15990/67

संस्थापक संपादक: स्व. श्री चिरंजीव जोशी 'सरोज'

हिन्दी पाक्षिक

वर्ष-60 अंक-10 | जयपुर, शनिवार, 31 अक्टूबर, 2026 | मूल्य- 10 रुपए | पृष्ठ- 8

सत्ता का अहंकार और मर्यादा विहीन होता लोकतंत्र

इस पक्ष का विशेष संपादकीय 'विनोद जोशी' द्वारा

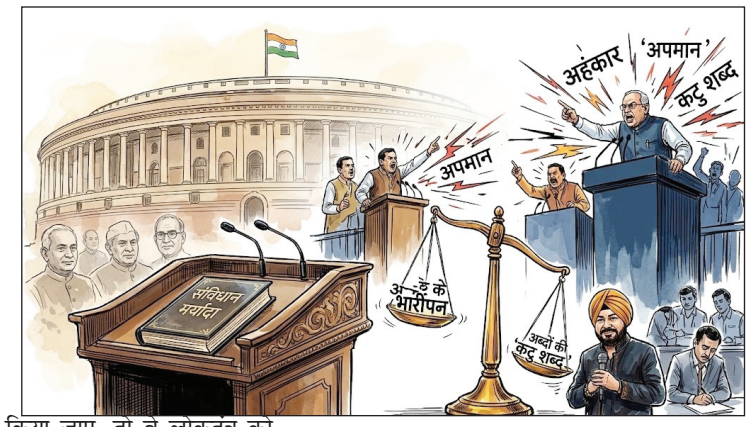


आकाश के उस पार भी एक दुनिया है, जहां शब्दों के घाव भरे नहीं भरते। सार्वजनिक जीवन में जब शालीनता की जगह कटुता और अहंकार ले ले, तो समाज का नैतिक ढांचा चरमराने लगता है।

लोकतंत्र की जीवंतता उसके संवाद की गरिमा में ही निहित होती है। मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हों, यदि उन्हें शालीनता और परस्पर सम्मान की चादर में लपेटकर प्रस्तुत किया जाए, तो वे लोकतंत्र को परिपक्व बनाते हैं। इसके विपरीत, जब सत्ता की हनक और चुनावी लाभ की चाहत सार्वजनिक भाषा की सीमाओं को रौंदने लगे..तो वह संवाद नहीं, बल्कि सामूहिक पतन का परिचायक बन जाता है। दुर्भाग्यवश, आज भारतीय राजनीति और सार्वजनिक विमर्श इसी असहज मोड़ पर खड़े नजर आते हैं।

हाल ही में उत्तराखंड के नई टिहरी में सरकार प्रायोजित पर्यटन मेले के दौरान जो कुछ घटा, वह इसी अहंकार की एक अशोभनीय बानगी है। मंच पर देश के जाने-माने गायक दलेर मेहंदी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तभी राज्य सरकार के एक मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर चढ़ आए। उन्होंने सरेआम माइक थामकर कलाकार पर नशे में होने और केवल रिकॉर्डेड गानों पर होंठ हिलाने (लिप-सिंकिंग) के अपुष्ट आरोप लगाए। बात यहीं नहीं रुकी; मंत्री महोदय ने उन्हें दी गई 35 लाख रुपये की फीस का सार्वजनिक रूप से ताना मारकर यह जतलाने की कोशिश की कि पैसे के बल पर किसी के आत्मसम्मान को भी कुचला जा सकता है। यह संभव है कि कलाकार अस्वस्थ रहा हो या प्रस्तुति अपेक्षा के अनुरूप न रही हो, किंतु क्या मंच के पीछे जाकर शिष्टता से बात करना संभव नहीं था? एक प्रतिष्ठित कलाकार को भरी महफिल में अपमानित करना वास्तव में

शेष भाग पृष्ठ 2 पर



दिल्ली की तयशुदा पटकथा और अनिश्चितता की नई आहट

क्या राहुल गांधी और सीजेपी बदलेंगे समीकरण?

देश की राजनीति पर विनोद जोशी की टिप्पणी

पिछले 12 साल से एक लीक पर चल रही देश की राजनीति अब कुछ-कुछ अलग रंग बदलती दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति के पीछे ठहरी राजनीति अब अपनी चाल बदलने को तैयार दिख रही है; लेकिन क्या चरित्र भी बदलेगी यह अभी भविष्य के गर्भ में है। भारतीय राजनीति की दशा और दिशा अभी दोनों ही अनिश्चित सी दिखाई दे रही है। यह निश्चित है कि सिर्फ एक ध्रुव याने मोदी नाम पर टिकी राजनीति अब अंगड़ाई लेती दिखाई दे रही है। हाल-फिलहाल कोई एक ध्रुव तो नहीं कहा जा सकता जो इस नाम के सामने अकेला खड़ा है। इस सब के बावजूद जेन-जी के आंदोलन ने विपक्ष को नया जीवनदान दिया है, कुछ नेताओं की विश्वसनीयता भी बनती दिखाई दे रही है। इसमें यह भी दिख रहा है कि विपक्ष आरंभिक हिचकिचाहट के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीछे अनमना सा खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत उनकी जेन-जी के बीच बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता है, हालांकि उनका रास्ता अभी भी बहुत लंबा और कंटकाकीर्ण है। नई बात यह है कि युवाओं के बीच से नेतृत्व निकलता दिखाई दे रहा है, जिसकी अगुआई नेहा बोरा जैसी वामपंथी विचार से निकली आग करती दिखाई दे रही है। हां, नरेंद्र मोदी और भाजपा का विकल्प तैयार है, यह मुगालता किसी को नहीं पालना चाहिए। जो भी विपक्ष है वह अभी उनसे बहुत पीछे है, रणनीतिक तौर पर भी और चुनावी संभावनाओं की कसौटी पर भी! बेशक, यह मानने में कोई बुराई नहीं है कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी जागृत विपक्ष अब देश की राजनीति में लौट रहा है।



एक विरोधाभास

शेष भाग पृष्ठ 3 पर

लूला दा सिल्वा चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित

ट्रंप समर्थक दक्षिणपंथी बोल्सनारो की हार

'नवयुग ब्यूरो' की लैटिन अमेरिकी राजनीति पर विशेष रिपोर्ट

ब्राजीलः राष्ट्रपति चुनाव



रियो डी जेनेरियो। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। मेक्सिको के बाद ब्राजील में वामपंथी विचारधारा के नजदीकी रखने वाले धड़ों की जीत ने लैटिन अमेरिकी देशों में ट्रंप समर्थक दक्षिणपंथी राजनीति के बढ़ते प्रभाव को रोक दिया है। ब्राजील में लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत का महत्त्व इसी बात में देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने लूला के धुर विरोधी दक्षिणपंथी फ्लावियो बोल्सोनारो को खुला समर्थन देते हुए ब्राजीली जनता से उन्हें वोट देने की अपील की थी। लूला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं। उनकी जीत से लैटिन अमेरिका में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने वालों को राहत मिलेगी।

चुनाव के अंतिम दिन बेहद तनावपूर्ण हालात में मतदान का समय दो घंटे के लिए निर्वाचन अदालत ने दोनों पक्षों के औपचारिक अनुरोध के बाद बढ़ाया था। सभी वोटों की गिनती पूरी होने के बाद निर्वाचन अदालत ने नतीजे घोषित करते हुए कहा कि लूला को 51.8 फीसदी वोट मिले। उन्होंने सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो को करीब 44 लाख वोटों से पीछे छोड़ दिया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव के पहले चरण में बोल्सनारो ने 47 प्रतिशत वोट लेकर लूला पर 2 प्रतिशत वोटों की बढ़त ली थी, लेकिन चुनाव के दूसरे दौर में लूला ने ट्रंप विरोध को अपना हथियार बनाया और 51.79 प्रतिशत वोट हासिल कर अपनी जीत सुनिश्चित की। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी फ्लेविओ बोल्सनारो को 48.21 प्रतिशत वोट मिले। लूला का नया कार्यकाल 5 जनवरी 2027 से शुरू होगा। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि बोल्सनारो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, वे निर्वाचन अदालत में चुनाव के नतीजों के विरुद्ध अपील करेंगे।

जीत के बाद साओ पाउलो में समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए लूला ने कहा कि वह सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार उनके चुने जाने से लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने ब्राजील की जनता द्वारा चुनी गई रूढ़िवादी

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

प्रथम पृष्ठ का शेष भाग... ब्राजील: राष्ट्रपति चुनाव

विचारधारा वाली कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने और देश के सभी 21.5 करोड़ नागरिकों के लिए शासन चलाने का वादा किया। लूला ने कहा कि उन्होंने अपने चुनाव अभियान ने मतदाताओं को यह समझाने में सफलता हासिल की कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की भी मांग की। उनका कहना था कि ब्राजील ने इन प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले विदेशी हस्तक्षेप को नाकाम किया है। लूला ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, 'ब्राजील किसी की जागीर नहीं है।'

पहले चरण के मतदान के बाद बोल्सोनारो को जीत की उम्मीद थी। हार ने उन्हें नतीजों पर अंगुली उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन नतीजों को 'स्वीकार करना असंभव' है। बोल्सोनारो अब चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनका तर्क है कि 'खेल के नियम बदल दिए गए थे।' उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर है, जिसके तहत मतदान का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया था।

यह फैसला असामान्य जरूर था, लेकिन इसके लिए लूला और बोल्सोनारो, दोनों के चुनावी अभियानों की टीमों ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। लूला की जीत लैटिन अमेरिका में उभरते उस रुझान के विपरीत है, जिसमें दक्षिणपंथी झुकाव वाले और ट्रंप के सहयोगी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। लूला के राष्ट्रपति बने रहने के साथ ही इस क्षेत्र के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों ब्राजील और मेक्सिको में वामपंथी झुकाव वाले नेता सत्ता में रहेंगे। इस जीत से ब्राजील अमेरिका से स्वतंत्र अपनी स्थिति बनाए रख सकेगा। ब्राजील की अर्थव्यवस्था का सालाना आकार 2.6 लाख करोड़ डॉलर है। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब ट्रंप ने ब्राजील पर अधिक आयात शुल्क लगाए हैं।

चुनाव नतीजों के बाद साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में लोग सड़कों पर जमा हुए. लूला के चुनाव प्रचार अभियान ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अपनी पत्नी और फर्स्ट लेडी रोजांगेला दा सिल्वा तथा सहयोगियों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। उन्होंने लाल रंग के सितारे के आकार का चश्मा पहन रखा था। इस महीने की शुरुआत में हुए पहले दौर के मतदान में बोल्सोनारो को लूला से 22 लाख से अधिक वोट ज्यादा मिले थे। एपी के मुताबिक, 1985 में सैन्य तानाशाही समाप्त होने के बाद लूला ऐसे पहले उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पहले दौर में दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव जीता।

मुद्दे क्या थे?

मतदाताओं के सामने महंगाई और अपराध प्रमुख चिंताएं थीं। बोल्सोनारो ने अपने चुनाव अभियान में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था। उन्होंने खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करने का भी आश्वासन दिया था। वहीं, लूला ने उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जिन्होंने अभी तक किसी उम्मीदवार को चुनने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने परिवारों की मदद के लिए महंगी योजनाओं पर खर्च किया। दोनों नेताओं को अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा है। बोल्सोनारो का नाम ब्राजील के एक बड़े घोटाले से भी जुड़ा रहा है।





पहले दौर के नतीजों के बाद लूला ने अपने चुनाव अभियान की रणनीति बदली। उन्होंने युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की, लोकतांत्रिक मूल्यों और अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड के समर्थन में लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा और बोल्सोनारो की एक और सरकार बनने के संभावित परिणामों को लेकर आगाह किया। साथ ही, उन्होंने अपनी सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाया। अमेरिकी हस्तक्षेप की आशंका ने भी लूला को मजबूती प्रदान की।

लूला की राजनीति

यह लूला के राजनीतिक करियर की संभवत: आखिरी चुनावी जीत होगी। उन्होंने 1970 के दशक में ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने वर्कर्स पार्टी की स्थापना में मदद की। लूला ने इस पार्टी की ओर से तीन बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। 2002 में उन्हें पहली बार जीत मिली और चार साल बाद वे दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। 2010 में उनकी सरकार में मंत्री रहीं डिल्मा रूसेफ ने उनकी जगह ली। रूसेफ 2014 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गईं। हालांकि, लेखा-जोखा संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर 2016 में उन्हें पद से हटा दिया गया। उस समय भ्रष्टाचार के आरोपों की एक व्यापक जांच चल रही थी, जिसमें लूला का नाम भी सामने आया था।

लूला ने 2018 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी साल मार्च में एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 580 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा किया गया। बाद में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी। इसके बाद लूला पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रमुख आलोचकों में शामिल हो गए। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बोल्सोनारो को बेहद करीबी मुकाबले में हराया था। 80 साल की उम्र में लूला अब अमेरिका महाद्वीप के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपतियों में शामिल हैं। इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्तेगा भी हैं, जिनकी उम्र भी 80 साल है।

प्रथम पृष्ठ का शेष भाग सत्ता का अहंकार और मर्यादा विहीन होता लोकतंत्र

उस प्रशासनिक व राजनीतिक असंवेदनशीलता को उजागर करता है, जहां पद को विशेषाधिकार और अहंकार का लाइसेंस मान लिया गया है।

यह कोई अकेली घटना नहीं है। सत्ता के मद में चूर जनप्रतिनिधियों का यह व्यवहार सबसे अधिक नौकरशाही और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति देखने को मिलता रहा है। कभी किसी विधायक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर को पुल की रेलिंग से बांधकर उस पर कीचड़ उड़ेला जाता है..तो कभी कोई जनप्रतिनिधि अधिकारियों को खुलेआम 'आलसी' और 'नाकाबिल' कहकर सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाता है। कहीं बिजली-पानी के कनेक्शन काटने की धमकियां दी जाती हैं, तो कहीं अधिकारियों और महिला पुलिसकर्मियों तक पर शारीरिक हमले की घटनाएं सामने आती हैं..क्या इन्हें सामान्य रोष या असंतोष का प्रदर्शन कह कर टाला जा सकता है? लेकिन इससे बड़ा सवाल यह भी सामने आता है कि क्या हमारे समाज और राजनीति का चरित्र यही रहा है? इस सवाल के जवाब में आपको-हमको बहुत कुछ दिखाई देना चाहिए..नहीं दिखाई दे तो हम और आप भी उसी 'धृतराष्ट्री शासन व्यवस्था' के अंग हैं, जिन्हें शकुनि कि कुटिल चालों में राजनीति शास्त्र के दर्शन होते थे!

शीर्ष नेतृत्व ही मर्यादाविहीन!

जब शीर्ष नेतृत्व ही मर्यादाओं की सीमाएं लांघने लगे, तो नीचे की कतारों में शालीनता की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। भारतीय राजनीति ने वह दौर भी देखा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों के मंच से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संदर्भ में 'कांग्रेस की विधवा' और 'जर्सी गाय' जैसे अत्यंत अशोभनीय और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। यह भाषा देश के सर्वोच्च पद की गरिमा और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों के विपरीत थी। वहीं दूसरी ओर, प्रतिपक्ष भी इस भाषाई पतन की दौड़ में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई कटु और आपत्तिजनक व्यक्तिगत उपमाओं ने यह दिखा दिया कि चुनावी तालियां बटोरने के लिए दोनों ही पक्ष किस हद तक गिर सकते हैं। जब देश के शीर्ष नेता ही मर्यादाओं को ताक पर रख दें, तो वे जाने-अनजाने पूरे समाज को असहिष्णुता और अभद्रता की ओर धकेल रहे होते हैं। आज भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर सबको प्रधानमंत्री की मर्यादा याद रही है, लेकिन क्या राजीव गांधी, उन्हें छोड़िए मनमोहन सिंह जैसे विश्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का अपमान वो भी खुलेआम लोकसभा में भुला दिया जाएगा? बोया पेड़ बबूल का..आम कहाँ से होय!

पतन का मूल

इस पतन के मूल में राजनीति का वह विकृत रूप है जहां वैचारिक निष्ठा, जनसेवा और बौद्धिक क्षमता के बजाय केवल 'जीतने की क्षमता' (विनेबिलिटी) को टिकट का आधार बना दिया गया है। चुनाव आयोग के हलफनामों और विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि लगभग 30 प्रतिशत मौजूदा सांसदों और विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब राजनीति में धनबल और बाहुबल को ही सफलता की कुंजी मान लिया जाएगा, तो उस व्यवस्था से शालीन आचरण की अपेक्षा करना मृगमरीचिका ही है। अपराधियों से भरी विधायिकाओं (यह हमारा कथ्य नहीं है, स्वयं उन्हीं निर्वाचित महानुभावों के शपथ पत्रों का निचोड़ है) से यह आशा कितनी जायज है..देश के हर विचारवान नागरिक को सोचना चाहिए!

परंपरा तो समृद्ध है, लेकिन..

हालांकि, भारतीय संसदीय इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे पास ऐसे कई सुनहरे अध्याय हैं जहां वैचारिक विरोध की ज्वाला तो प्रचंड थी, पर भाषा की मर्यादा कभी खंडित नहीं हुई। डॉ. राममनोहर लोहिया संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के सबसे प्रखर आलोचक थे, किंतु जब व्यक्तिगत संबंधों और संवाद की बात आती थी, तो दोनों एक-दूसरे की बौद्धिक गरिमा का पूरा सम्मान करते थे। पंडित नेहरू ने युवा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रखर भाषण को सुनकर न केवल उनकी प्रशंसा की थी, बल्कि उनमें देश का भावी प्रधानमंत्री भी देखा था।

इसी प्रकार, जब 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (जिनेवा) में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखना था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा था। वाजपेयी जी और इंद्रजीत गुप्त जैसे दिग्गजों ने संसद में अपनी तीखी से तीखी असहमतियों को जिस साहित्यिक सौम्यता, व्यंग्य और गरिमा के साथ व्यक्त किया, उसने भारतीय संसदीय प्रणाली का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। वहां प्रहार विचारों पर था, व्यक्ति के आत्मसम्मान पर नहीं।

सार्वजनिक जीवन में शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे समाज के आचरण की दिशा तय करते हैं। सत्ताएं आती-जाती रहेंगी, चुनावी जीत-हार के आंकड़े बदलते रहेंगे, किंतु सार्वजनिक मंचों से बोले गए कटु और अमर्यादित शब्द इतिहास के पन्नों पर अमिट दाग छोड़ जाते हैं। राजनेताओं को यह समझना होगा कि जनता का विश्वास जीतना और उसका नेतृत्व करना एक गंभीर उत्तरदायित्व है। यदि हमने अपने संवाद में शालीनता, विनम्रता और मर्यादा को तुरंत पुन: स्थापित नहीं किया, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो तर्क के बजाय केवल तकरार और अहंकार की भाषा समझेगी।

संयुक्त राष्ट्र की साख पर सवाल, सुधार से ही बचेगी प्रतिष्ठा!

धनी देशों के चंगुल से मुक्ति, समानता और न्याय के लिए प्रतिबद्धता जरूरी

संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर 2026) पर विशेष



ललित गर्ग



संयुक्त राष्ट्र दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उत्सव नहीं, बल्कि विश्व शांति, मानवाधिकारों, न्याय, समानता और राष्ट्रों के बीच सहयोग के उन संकल्पों को याद करने का अवसर है, जिनके आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद इस संगठन की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू होने के साथ दुनिया ने एक ऐसी व्यवस्था की उम्मीद की थी, जिसमें युद्ध की जगह संवाद, टकराव की जगह सहयोग और शक्ति के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता मिलेगी। किंतु आज, जब दुनिया अनेक युद्धों, आतंकवाद, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और मानवीय संकटों से जूझ रही है, तब संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। जिस संगठन से विश्व समुदाय को न्याय की अपेक्षा थी, उसकी कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आने लगे तो आत्ममंथन अनिवार्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों को नकारना उचित नहीं होगा। उसने अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराया, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के माध्यम से मानवीय गरिमा के वैश्विक मानक स्थापित किए और अनेक देशों में शांतिरक्षा अभियानों के जरिए स्थिरता बहाल करने का प्रयास किया। विश्व स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शिक्षा, शरणार्थियों की सहायता तथा सतत विकास के क्षेत्रों में उसकी विभिन्न संस्थाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके बावजूद मूल प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने सबसे महत्वपूर्ण दायित्व-युद्ध रोकने, आतंकवाद पर प्रभावी अंकुश लगाने और सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाया है? आज का अनुभव इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता।

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सुरक्षा परिषद की संरचना में दिखाई देती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को प्राप्त वीटो अधिकार कई बार वैश्विक शांति से अधिक उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा का माध्यम बन जाता है। जब किसी युद्ध या मानवीय त्रासदी पर प्रभावी निर्णय भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण रुक जाता है, तब संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएं और अपीलें अपनी नैतिक शक्ति खोने लगती हैं। गाजा, यूक्रेन और सीरिया जैसे संघर्षों ने यह प्रश्न तीखा किया है कि क्या विश्व शांति का दायित्व निभाने वाला संगठन वास्तव में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है? विडंबना यह है कि दुनिया बदल गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की निर्णय व्यवस्था काफी हद तक उसी पुराने शक्ति-संतुलन में बंधी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों का ताजा उदाहरण दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह डी-कंपनी से जुड़ा विवाद है। आतंकवाद और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक बेन साल की रिपोर्ट में डी-कंपनी को 'भारत आधारित' आपराधिक गिरोह बताया गया। भारत ने 21 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में इस विवरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और संगठन की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। भारतीय प्रतिनिधि रघु पुरी ने दाऊद के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े इतिहास और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में दर्ज तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि दाऊद भारत में वांछित अपराधी है और भारत के अनुसार पाकिस्तान में रह रहा है।

यह प्रकरण इसलिए गंभीर है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील विषय पर तथ्यात्मक शुद्धता और निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी आतंकवादी गिरोह की भौगोलिक पहचान को लेकर गलत या अधूरी जानकारी सामने आना केवल एक रिपोर्ट की त्रुटि नहीं, बल्कि विशेष प्रतिवेदकों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, किंतु स्वतंत्रता का अर्थ तथ्यों और उत्तरदायित्व से मुक्त होना नहीं है। इसी प्रकार मानवाधिकारों के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। मानवाधिकार किसी राष्ट्र की सीमाओं में कैद विषय नहीं हैं, लेकिन उनकी रक्षा के नाम पर किसी देश के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने से पहले प्रमाणों, परिस्थितियों और आतंकवाद से प्रभावित नागरिकों के अधिकारों को समान गंभीरता से देखना चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों के मानवाधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने आतंकवाद से निपटने के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति के अधिकार। यदि आतंकवाद के प्रायोजकों, हिंसा के जिम्मेदार लोगों और पीड़ितों के प्रति दृष्टिकोण में असमानता दिखाई देती है, तो निष्पक्षता पर संदेह स्वाभाविक है।

संयुक्त राष्ट्र के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती प्रतिनिधित्व की असमानता है। भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की बढ़ती वैश्विक भूमिका के बावजूद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी प्रयासों की विश्वसनीयता का प्रश्न है। हालांकि किसी एक रिपोर्ट की गलती से पूरे संगठन के प्रत्येक कार्य को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी त्रुटियों की जांच, सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। वीटो व्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं हो पाया है। दुनिया की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली व्यवस्था के बिना संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक बनाना कठिन है। आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति, युद्धविराम की प्रभावी व्यवस्था, मानवीय सहायता की निर्बाध उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय कानून के समान अनुपालन को भी प्राथमिकता देनी होगी। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर आत्ममंथन का वास्तविक अर्थ केवल उसकी उपलब्धियों का गुणगान करना नहीं, बल्कि उसकी कमियों को स्वीकार कर सुधार का संकल्प लेना है। संगठन को अपने निर्णयों में पारदर्शिता, रिपोर्टों में तथ्यात्मक शुद्धता, अधिकारियों की जवाबदेही और सभी देशों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। वीटो अधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने, सुरक्षा परिषद के विस्तार और आतंकवाद के विरुद्ध दोहरे मानदंड समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी।

आज जब दुनिया युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, मानवीय संकट और राष्ट्रों के बीच बढ़ते अविश्वास के दौर से गुजर रही है, तब संयुक्त राष्ट्र दिवस की प्रासंगिकता और जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यह दिवस केवल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का स्मरण नहीं, बल्कि विश्व शांति, सह-अस्तित्व, मानवीय गरिमा और वैश्विक सहयोग के संकल्प को दोहराने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के माध्यम से यह सिद्ध करना होगा कि वह शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों का नहीं, बल्कि समूची मानवता के न्याय और सुरक्षा का प्रहरी है। उसका वास्तविक दायित्व युद्ध रोकना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना और शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया पर शासन करना नहीं, बल्कि दुनिया को युद्ध, अन्याय और विनाश से बचाने में सहयोग देना है। उसकी प्रतिष्ठा केवल उसके घोषणापत्रों से नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में किए गए निष्पक्ष और प्रभावी कार्यों से तय होगी। 24 अक्टूबर का संदेश तभी सार्थक होगा, जब यह संगठन अपनी मूल भावना की ओर लौटे और शक्तिशाली तथा कमजोर, छोटे तथा बड़े, सभी राष्ट्रों के लिए समान न्याय का भरोसेमंद मंच बने। संयुक्त राष्ट्र को केवल अस्तित्व नहीं, अपनी प्रासंगिकता भी बचानी है और इसके लिए पक्षपात से मुक्ति, जवाबदेही तथा आमूलचूल सुधार अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेष भाग- दिल्ली की तयशुदा पटकथा और अनिश्चितता की नई आहट

भारतीय राजनीति के पिछले एक दशक से अधिक के सफर का सबसे विचित्र विरोधाभास यही रहा है कि सत्ता में बैठी भाजपा प्रतिपक्ष की तरह आक्रामक होकर एक पराजित अतीत से लड़ती रही और मुख्य विपक्षी कांग्रेस इस मुगालते में बैठी रही कि गद्दी तो उसी की बपौती है, जिसे बस कुछ वक्त के लिए किसी ने छीन लिया है। एक दल जा चुकी सत्ता पर हमले बोलकर वैधता तलाशता रहा, तो दूसरा यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि उसकी सल्तनत ढह चुकी है। दोनों ने एक-दूसरे के सहारे अपनी-अपनी राजनीतिक सहूलियत का एक आरामदायक दायरा तैयार कर लिया, जहां टीवी स्टूडियो के शोर और तयशुदा बहसों के बीच जनसरोकार कहीं नेपथ्य में चले गए। जनसरोकार की बात तो दूर की कौड़ी है, देश की राजनीति का विपक्षविहीन होना बहुत बड़ी त्रासदी बन गया। मोदी-शाह के नेतृत्व में भाजपा ने खुद को विपक्ष और कांग्रेस को सत्तापक्ष की तरह लगातार कठघरे में खड़ा रखा। एक अर्से तक कांग्रेस इस जाल को खुशी-खुशी ढोती रही, उसे यह समझने में 8-10 साल लग गए कि सत्ता में कोई और है! वे सत्ता में बैठे शहंशाहों की तरह मकड़जाल में जले बुनती रही।

दिल्ली के आगे भी देश!

मगर दिल्ली के इस अभ्यस्त शोर से दूर, जब आप छोटे शहरों, गांवों, ढाणियों और पहाड़ों में आम नागरिकों के बीच बैठते हैं, तो फिजा में एक अलग तरह की सुगबुगाहट महसूस होती है। कॉक्रोच जनता पार्टी की सफलता कोई एकाएक जलजला नहीं है, यह वही धीमे-धीमे सुलगती आंच है जिसे कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष न समझ पाया और न अपने दायरे में ला पाया। यहां तक कि दूरदराज हिमालयीवादियों में बसे जिस कश्मीर को दिल्ली की सत्ता केवल एक 'समस्या' के चश्मे से देखती रही, आज वही वादी दिल्ली के भविष्य का गणित सुलझाने में जुटी है। लोगों में निराशा या कोरी तल्खी नहीं, बल्कि यह जानने की एक स्वाभाविक ललक है कि आगे क्या कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? क्या सत्तारूढ़ दल की अभेद्य छवि में कोई दरार पड़ रही है?

'कॉक्रोच जनता पार्टी'

इसी चौपाल-चर्चा के केंद्र में उभरती है 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) और उसकी जमीन। चुनावी शुचिता, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका और युवा आकांक्षाओं को लेकर सीजेपी जिस आक्रामकता से सड़कों पर उतरी है, वह महज नौजवानों का क्षणिक उबाल नहीं दिखता।

कॉक्रोच का रूपक ही अपने-आप में कठोरतम परिस्थितियों में भी टिके रहने की जिद का प्रतीक है। यही जिद सत्ता प्रतिष्ठान के माथे पर सिलवटें ला रही है। अचानक अनजान से युवाओं को देश की राजनीति की मुख्यधारा के नेतृत्व की पंक्ति में स्थान दिला पाना, वह भी विश्वसनीयता के साथ सीजेपी की बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सबके बावजूद संगठनात्मक ढांचे की गैरमौजूदगी, दीर्घकालीन संघर्ष में टिकने की रणनीति और खुद की विकल्प के रूप में स्वीकार्यता अभी भी दूर की कौड़ी है। देश में सत्ता प्रतिष्ठान पर मोदी-शाह के नेतृत्व में भाजपा न सिर्फ संगठनात्मक रूप से लगभग अजेय परिस्थिति में दिखाई देती है, वरन राजनीति के लिए आवश्यक धन-बल में वह अभेद्य भी है। यही वह कड़ी है, जो भारत के जेन-जी आंदोलन को अन्य देशों के जेन-जी आंदोलनों से अलग करता है। इस देश में अभी वह स्थिति नहीं है कि सिर्फ जेन-जी या कोई एक पीढ़ी अकेले ही सत्तारूढ़ दल को चुनावी शिकस्त दे सके, एक मजबूत गठबंधन ही एकमात्र उपाय है। और, यहीं से युवा असंतोष की सफलता पर संदेह के बादल खड़े हो जाते हैं।

भारतीय शेयर बाजार : विश्व के प्राथमिक पूंजी निवेश बाजार से बाहर होने का खतरा!

भारतीय पूंजी बाजार पर 'नवयुग' की रिपोर्ट

भारतीय शेयरों में बिकवाली का पैमाना और कमतर प्रदर्शन (अंडरपरफॉरमेंस) की तीव्रता अस्थिर व असहनीय है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का टूटता भरोसा पिछले 50 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन को इंगित कर रहा है। अभी कुछ समय पहले तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के उद्घोष का अंतरराष्ट्रीय बाजार में विरोध नहीं होता था, बल्कि वह चर्चा का विषय भी था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि भारत अब वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा नहीं रहा। सितंबर 2024 में भारतीय बाजार के चरम बिंदु पर पहुंचने के बाद से विदेशी संस्थागत और पोर्टफोलियो निवेशकों ने 65 बिलियन की शुद्ध निकासी की है। पूंजी बाजार का पिछले एक दशक का ईमानदारी से तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाए, तो भारत को कुल शुद्ध पूंजी निवेश एक बड़ा शून्य है, यह लगभग अविश्वसनीय आंकड़ा है, क्योंकि पिछले एक दशक में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान इन कोई भी विश्वसनीय आंकड़ा प्रसारित ही नहीं किया। यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है, विश्वगुरु और विश्वनेतृत्व के कथात्मक व्याख्यान ने अर्थव्यवस्था की असलियत को सामने आने ही नहीं दिया है।



विदेशी निवेश की हकीकत

विदेशी निवेशकों के स्वामित्व वाली भारतीय इक्विटी का कुल मूल्य 930 बिलियन से गिरकर लगभग 675 बिलियन हो गया है, बाजार के प्रतिशत के रूप में विदेशी स्वामित्व अब 15 साल के निचले स्तर पर आ गया है। भारत अब सभी वैश्विक निवेशकों के लिए एक सर्वसम्मत अंडरवेट देश बन चुका है और हमारा भार (वेटिंग) सितंबर 2024 के 21 प्रतिशत से घटकर आज लगभग 10 प्रतिशत (रूष्ठड्ड इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स) रह गया है। विश्व बाजार में अकेले एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) का बेंचमार्क भार पूरे भारत के कुल भार से 50 प्रतिशत अधिक है! विश्व के उभरते बाजार के तीन दिग्गज – टीएसएमसी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिस्क मिलकर सूचकांक का 30 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जो कि भारत के भार से लगभग तीन गुना है। यह हकीकत आंख खोल देने वाली है, बशर्ते हम अपने गोयबल्सी प्रचारतंत्र के परे देखने कि कुछ क्षमता बरकरार रख पाए हों?

पिछले बहुत से वर्षों में पूंजी बाजार का अभूतपूर्व खराब प्रदर्शन (अंडरपरफॉरमेंस) भी देखा गया है। सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर के बाद से डॉलर के संदर्भ में भारतीय इक्विटी में लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट आई है, भले ही उभरते बाजारों याने इमर्जिंग मार्केट सूचकांकों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो। भारतीय इक्विटी बाजार ने पिछले दो वर्षों में ही 7,500 आधार अंकों (75 प्रतिशत अंक) का कम प्रदर्शन किया है। भारत में पूंजी याने इक्विटी बाजार के खुलने के बाद का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। इसने कई लोगों के व्यवसाय नष्ट कर दिए हैं और फंड्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे कई फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 24 महीनों में केवल भारत में ओवरवेट रहने के कारण अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को बर्बाद कर दिया।

आंकड़ों का मकड़जाल

सामान्य परिस्थितियों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उथल पुथल के बीच सूचकांकों, आंकड़ों और संख्याओं को अर्थव्यवस्था के विपरीत संकेतकों के रूप में देखा जा सकता है। हमारे इक्विटी बाजार की बिकवाली का पैमाना और खराब प्रदर्शन की गति व तीव्रता अस्थिर है। आंकड़ों में झोल दिखता है जब एशिया की तीन कंपनियों का सूचकांक भार भारत जैसे आकार और क्षमता वाले देश के भार से तीन गुना दिखाई देता है। इन तीन कंपनियों का संयुक्त सूचकांक भार 30 प्रतिशत कैसे हो सकता है, जो भारत और चीन के संयुक्त भार 30.5 प्रतिशत के लगभग बराबर दिखाई देता है? लगता यही है आंकड़ों के मकड़ जाल में कुछ तो गलत है। यह हास्यास्पद लगता है कि तीन एशियाई प्रौद्योगिकी कंपनियों का सूचकांक भार दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी के लगभग बराबर हो सकता है। यह एक आदर्श विपरीत संकेतक है। आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण भारत के पूंजी बाजार में जल्द वापसी की संभावनाएं भी दिखाते हैं, इसके बावजूद दूसरे कुछ आंकड़े और जमीनी हकीकत चिंता भी पैदा करती हैं।

वैश्विक निवेशक अनमने!

वैश्विक बाजार में यह सवाल पिछले बीस सालों में पहली बार पूछा जा रहा है कि भारत-समर्पित आवंटन (इंडिया-डेडिकेटेड एलोकेशन) की आवश्यकता है क्या? कई पूंजी आवंटक (एलोकेटर्स) अब यह नहीं मानते कि भारत इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए अलग से निवेश रखा जाए। भारतीय पूंजी बाजार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जोखिम उठाने और खासतौर पर भारत पर दांव लगाने की जहमत क्यों उठाई जाए? यह बातचीत वर्षों बाद सामने आई है। बीस साल पहले, प्रत्येक एलोकेटर के पास चीन और ब्राजील में समर्पित पूंजी होती थी, और भारत एक बहस का विषय था। समय के साथ, यह एक स्थापित राय बन गई कि उभरते बाजारों में निवेश करने के लिए आपको भारत, ग्रेटर चीन और ब्राजील के लिए समर्पित फंड की आवश्यकता थी। यदि एलोकेटर्स अब भारत-विशिष्ट दांव लगाने के लिए अनिच्छुक हैं, तो यह एक बड़ा नकारात्मक पहलू है और यह देश में आने वाली विदेशी इक्विटी की मात्रा के साथ-साथ पूंजी की विविधता को भी सीमित कर देगा। गैर-समर्पित निवेश स्वाभाविक रूप से अधिक चक्रीय होता है।

सोच में बदलाव?

तो सोच में यह बदलाव क्यों आया है? सबसे पहले, भारत के ईएम भार में गिरावट। केवल 10 प्रतिशत पर, हम उस स्तर के आधे रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे, और तीन देश ताइवान, कोरिया और चीन ईएम सूचकांक का 70 प्रतिशत हिस्सा हैं। क्या आपको वास्तव में भारत की परवाह करने की आवश्यकता है? भारत को लेकर गलत दांव लगाना भी वास्तव में बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं करेगा। पिछले 10 वर्षों में, भारत ने वैसे भी ईएम सूचकांकों की तुलना में सालाना लगभग 180 आधार अंकों का कम प्रदर्शन किया है। 20 साल के आधार पर भी, भारत ने केवल मामूली रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह आख्यान (नैरेटिव) कि आपको कंपनियों की गुणवत्ता, विकास की स्थिरता और उद्यमशीलता ऊर्जा के कारण भारत में होना चाहिए, अब खोता जा रहा है। यह विश्वास अब मौलिक रूप से कम हो गया है कि हमारे पास आने वाले दशकों में मजबूत वृद्धि का दौर है।

दूसरा, कई निवेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत पर्याप्त पूर्ण रिटर्न (एब्सोल्यूट रिटर्न) नहीं दे सकता है। उनकी गणना इस प्रकार है। रुपये में निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 20 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 10.5 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। लगभग 15 प्रतिशत के पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) के प्रभाव को मानते हुए (20 प्रतिशत की अल्पकालिक दर और 12.5 प्रतिशत की दीर्घकालिक दर का औसत), यह रिटर्न को घटाकर लगभग 8.9 प्रतिशत पर ले आता है। फिर, रुपये में लगभग 4 प्रतिशत के अवमूल्यन (पिछले 20 वर्षों का औसत) को मानते हुए, यह डॉलर के संदर्भ में रिटर्न को घटाकर लगभग 6 प्रतिशत पर ले आता है। जब अमेरिकी इक्विटी में 100 साल का वार्षिक रिटर्न लगभग 10 प्रतिशत है, तो 6 प्रतिशत के साथ क्यों परेशान हुआ जाए? तर्क यह भी दिया जाता है कि 25 साल का निफ्टी रिटर्न 10 प्रतिशत नहीं बल्कि लगभग 13.5 प्रतिशत है। निफ्टी का रिटर्न बाजार के वास्तविक रिटर्न को कम करके दिखाता है और मुद्रास्फीति के अंतर के कम होने को देखते हुए मुद्रा में 4 प्रतिशत की निरंतर गिरावट मान लेना तर्कसंगत नहीं है।

साथ ही, वर्तमान मूल्यांकन (वैल्यूएशन) को देखते हुए, क्या आप संयुक्त राज्य अमेरिका में लगातार 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं?

हम और हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री क्या सोचता हैं और क्या कहते हैं..इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निवेशक यही कह रहे हैं। सभी विदेशी निवेशक पूंजीगत लाभ कर को लेकर नाराज हैं। वे किसी अन्य प्रमुख क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) में ये कर नहीं चुकाते हैं। इससे अनुमानित दीर्घकालिक वार्षिक रिटर्न में लगभग 2 प्रतिशत की कमी आती है और लंबी अवधि के लिए देशों की तुलना करते समय यह एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। यह धारणा भी है कि भारत व्यापार करने के लिए एक जटिल जगह बना हुआ है। भारतीय सेवा प्रदाता वैश्विक निवेशकों की जोखिम और अनुपालन टीमों को डराने का अच्छा काम करते हैं। हालांकि यह अनुचित हो सकता है, लेकिन यह धारणा बनी रहती है।

भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सबसे बड़ा वैश्विक नुकसान उठाने वाले देश के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि एआई से पहले दुनिया में जनसांख्यिकी और कुशल व्हाइट-कॉलर कार्यबल के हमारे प्रमुख लाभ जैसे कारक अब अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, जो विश्व स्तर पर मूल्य निर्माण को गति दे रहे हैं, भारत में कमजोरी के क्षेत्र माने जाते हैं। कोई भी इस तर्क का खंडन कर सकता है, लेकिन कई एलोकेटर्स इस पर विश्वास करते हैं।

नीतिगत असमंजस

भारत बीच के असमंजस (नो-मैन्स लैंड) में भी फंस गया है, यह वैल्यू निवेशकों के लिए इतना सस्ता नहीं है कि वे भारी संख्या में आएं और न ही यह इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ग्रोथ निवेशकों को आकर्षित कर सके। यदि भारत एक स्वतंत्र परिसंपत्ति वर्ग (इंडिपेंडेंट एसेट क्लास) के रूप में अपना आकर्षण खो देता है, तो यह चिंता का कारण है। हम कम संरचनात्मक पूंजी आकर्षित करेंगे और वैश्विक एलोकेटर्स के लिए कम प्रासंगिक होंगे। मूलभूत रूप से पूंजी की कमी वाले देश के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। इक्विटी बाजार भारत के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हैं, यदि हम दीर्घकालिक पूंजी के समर्पित प्रवाह तक पहुंच खो देते हैं तो हम इसे कमजोर कर देंगे। हालांकि यह भी तथ्य है कि यह सब डाटा आधारित विपरीत संकेतक (कंट्रेरियन इंडिकेटर) अधिक दिखाई दे रहा है, उम्मीद की किरण इसी बात में छिपी है कि भारत को लेकर अधिक नकारात्मक सोच अभी आरंभिक अवस्था में है। लेकिन यह भी सच है कि हमें नीतिगत असमंजस से बाहर निकल कुछ ठोस निर्णयों की जरूरत होगी, यहीं पर सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

पूंजी में जब निराशा का माहौल हो तब किसी भी देश की केंद्रीय सरकार को अपने बाजारों को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक नैरेटिव बनाने में सकारात्मक भूमिका का वहन करना होता है, यही वह बिंदु है जहां से निवेशकों को अब और आशाएं नहीं दिखाई देती। पूंजी बाजार में तेजी और मंदी के अपने चक्र होते हैं, वहां हवा का रुख भी बदलता है। लेकिन इस सब के लिए पूंजी निवेशकों की प्राथमिक विचार सूची (कंसीडरेशन सेट) से और नीचे खिसकने से खुद को बचाना होगा।

जीडीपी का 7.8% सच, 2.6% का सवाल

86 से 80 लाख करोड़ की कहानी

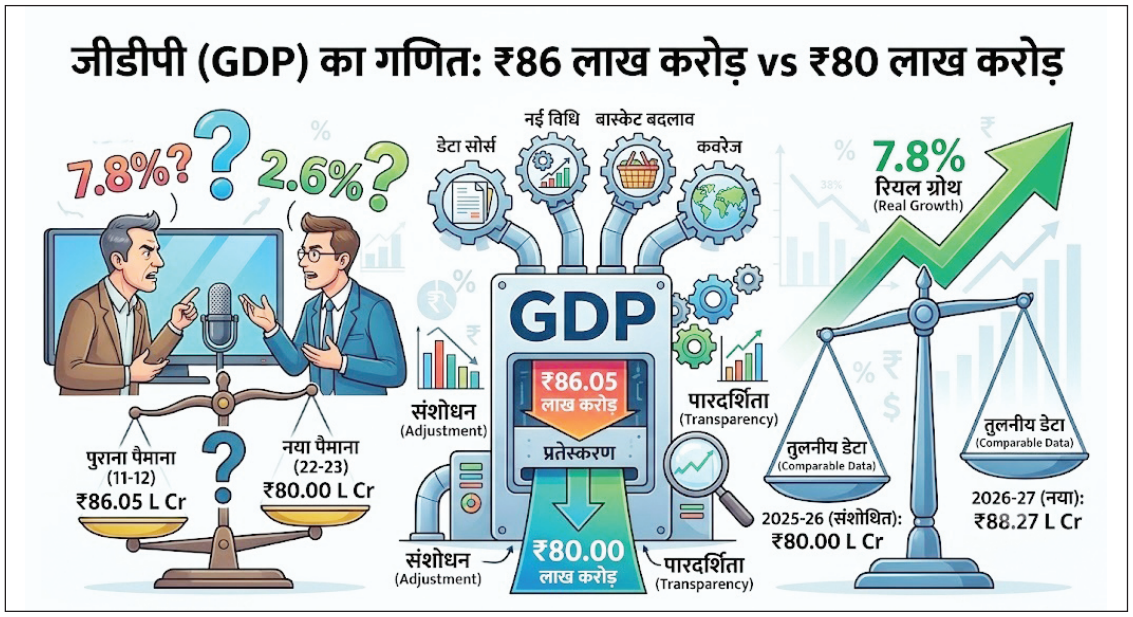
पंकज जायसवाल



अभी कुछ दिन पहले जब वित्तीय वर्ष 26-27 के पहली तिमाही जीडीपी आंकड़े के साथ रियल जीडीपी 7.8 फीसदी की घोषणा सरकार के द्वारा की गई तो इसके आलोचना में पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बयान ने इसे काफी विवादित बना दिया। मैंने इसी विवाद के पार्श्व में क्या सच्चाई है, इसे समझने और समझाने दोनों की कोशिश की है। मैंने, जीडीपी घोषणा के दिन सुभाष चंद्र गर्ग क्या कह गए और विवाद के बाद दिए अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, उसको भी सुना। दरअसल, जीडीपी घोषणा वाले दिन टीवी पर सुभाष चंद्र गर्ग ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, इस बात पर क्लेम किया कि सरकार को चूंकि इस तिमाही का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा दिखाना था, इसलिए पिछले वर्ष की पहली तिमाही का जीडीपी का डाटा 86.05 लाख करोड़ से घटाकर 80 लाख करोड़ कर दिया ताकि इस वित्त वर्ष के 88.27 लाख करोड़ से इसकी तुलना करें तो ग्रोथ ज्यादा दिखे। ऐसा कह कर उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर 7.8 के ग्रोथ को गलत बताते हुए नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ को 10.3 फीसदी की जगह 2.6 बताया।

हालांकि पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2026-27 की रियल जीडीपी 81.36 लाख करोड़ और पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलनीय रियल जीडीपी 75.46 लाख करोड़ है। इससे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत निकलती है। हालांकि इसके बाद दिए गए पॉडकास्ट इंटरव्यू में वह मंशा वाले सवाल से हट कर आंकड़ों की पारदर्शिता की बात करते दिखाई दिए और इस बात पर जोर दिया कि नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा 86.05 लाख से कैसे 80 लाख करोड़ पहुंचा, इसको सरकार को बताना चाहिए।

श्री गर्ग के बयान के बाद मीडिया ने भी गलत तरीके से इसे पेश किया कि जीडीपी ग्रोथ 7.8 फीसदी नहीं, 2.6 फीसदी है जबकि उस दिन श्री गर्ग 2.6 फीसदी नॉमिनल जीडीपी आंकड़े के लिए कह रहे थे। रियल जीडीपी के आंकड़े तो उनके हिसाब से शून्य आ रहे थे। चूंकि श्री गर्ग वित्त सचिव थे तो मीडिया विपक्ष सबने इनके बयान को गंभीरता से लिया और देश में जीडीपी के आंकड़े को लेकर भ्रम पैदा हो गया। मैंने अपने अध्ययन में पाया कि पहले दिन टीवी में बोलते वक़्त श्री गर्ग फंडामेंटली गलती कर गये। जब भी जीडीपी की नई सीरीज आती है उसकी विधि, उसके डाटा सोर्स, उसके डाटा बास्केट सब उन्नत हो जाते हैं। इसलिए दो अलग-अलग बेस वर्ष के सीरीज के जीडीपी डाटा एक दूसरे के लिए तुलनीय नहीं होते और अगर तुलनीय बनाना ही है तो या तो दो वर्ष के जीडीपी डाटा को किसी एक सीरीज के हिसाब से समायोजित करना पड़ेगा। ऐसे में या तो आप वर्ष 26-27 के आंकड़े को जो आपने नई बेस सीरीज 22-23 के हिसाब से निकालेये और फिर पुराने 11-12 सीरीज के हिसाब से निकाले गए डाटा 86.05 लाख करोड़ से तुलना करिए या आप 26-27 के डाटा को 22-23 के नए सीरीज के विधि, बास्केट और डाटा सोर्स के हिसाब से ही रहना दीजिये और पुराने सीरीज से निकाले गए वित्तीय वर्ष 25-26 के डेटा को नई बेस सीरीज के विधि, डाटा सोर्स और डाटा बास्केट के हिसाब से समायोजित कर नए डाटा से तुलना योग्य डाटा निकालिये। और सरकार ने यही किया।पहली तिमाही वर्ष 25-26 के डाटा को तुलनीय बनाने के लिए नई बेस सीरीज के गणना विधि, डाटा सोर्स और डाटा बास्केट के हिसाब से समायोजित कर 80 लाख करोड़ का डाटा निकाला और फिर तुलना की।



इसे मैं एक व्यावहारिक आंकड़े से समझाता हूं, कुछ वर्ष पूर्व भारत में बड़ी कंपनियों के लिए नए एकाउंटिंग मानक लागू हुए, जब ये लागू हुए तो वर्तमान वर्ष के लाभ हानि और बैलेंस शीट तो इस नए एकाउंटिंग मानक के हिसाब से बन गए और ऑडिट हो गए। चूंकि कंपनियों को अपने बैलेंस शीट में वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष दो वर्ष का डाटा दिखाना होता है तो वहां दिक्कत आ रही थी क्योंकि वर्तमान वर्ष का लाभ हानि और बैलेंस शीट नए लेखा मानक पर था और पिछले वर्ष का पूरा आंकड़ा पुराने लेखा मानक के हिसाब से था। इसलिए दोनों की तुलना बैलेंस शीट रीडर के लिए गलत हो जाता। ऐसे में वह रास्ता निकाला गया कि पिछले वर्ष के ऑडिटेड डाटा को भी नए लेखा मानक के हिसाब से ट्रांसलेट कर के ही बैलेंस शीट में दिखाए जाएं ना कि पुराने आंकड़े को जस का तस। और ऐसा कर के कंपनियों ने अपने पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान वर्ष के आंकड़े से तुलनीय बनाया। ऐसे में यह बहुत सामान्य है कि अगर दो वर्षों के डाटा में विधि, मानक, डाटा सोर्स या डाटा बास्केट बदला हुआ है तो दोनों में से किसी एक को तो समायोजित कर दोनों डाटा को एक मानक एक तराजू पर तो लाना ही पड़ेगा, तभी तुलना हो सकती है। अत: अगर संशोधित या समायोजित डाटा से तुलना हुई है तो इसमें कोई गलती नहीं हुई है यह उन्नत डाटा की प्रक्रिया में एक सामान्य घटना है। इसलिए मेरा मानना है कि अपने पहले टीवी बाइट में श्री गर्ग का तर्क सही नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे पॉडकास्ट में पारदर्शिता पर जोर दिया कि सरकार 86.05 लाख करोड़ का डाटा 80 लाख करोड़ कैसे हुआ, उसे बताये। उनका अगले जीडीपी का आंकड़ा अनुमानित जरूर है लेकिन मनमाना नहीं और यही कारण है कि जीडीपी के आंकड़े समय के साथ संशोधित होते हैं। जीडीपी में संशोधन होना सामान्य प्रक्रिया है। जीडीपी का पहला अनुमान उस समय उपलब्ध सीमित जानकारी के आधार पर तैयार होता है। समय बीतने के साथ अधिक विस्तृत और बेहतर आंकड़े उपलब्ध होते हैं। कंपनियों के वास्तविक परिणाम, सरकारी खातों की अधिक विस्तृत जानकारी, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, सर्वेक्षण और दूसरे प्रशासनिक आंकड़े बाद में उपलब्ध हो सकते हैं।

भारत में यह कोई नई परंपरा नहीं है। जीडीपी के लिए एडवांस अनुमानों, प्रोविशनल अनुमानों और संशोधित अनुमानों की व्यवस्थित प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। पहले पहला एडवांस अनुमान, दूसरा एडवांस अनुमान, प्रोविशनल अनुमान और उसके बाद पहला, दूसरा तथा तीसरा संशोधित अनुमानों के चरण थे लेकिन 2024 में दूसरे संशोधित अनुमान को अंतिम अनुमान मानते हुए तीसरे संशोधित अनुमान की पुरानी व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में सामान्यत: पांच प्रमुख चरण रह गए हैं। इसलिए जीडीपी का संशोधन होना अपने आप में न असामान्य है और न ही किसी गड़बड़ी का प्रमाण।

जब भी जीडीपी की नई सीरीज आती है उसकी विधि, उसके डाटा सोर्स, उसके डाटा बास्केट सब उन्नत हो जाते हैं। इसलिए दो अलग-अलग बेस वर्ष के सीरीज के जीडीपी डाटा एक दूसरे के लिए तुलनीय नहीं होते और अगर तुलनीय बनाना ही है तो एक सीरीज के हिसाब से समायोजित करना पड़ेगा।

मेरा मानना है कि संशोधन होना सामान्य है तो संशोधन के कारणों की पारदर्शी व्याख्या भी उतनी ही सामान्य और जरूरी होनी चाहिए और वो भी तब जब अंतर 6 लाख करोड़ जैसे बड़े आंकड़े के आसपास हो। चूंकि यह अंतर बड़ा है और एक पुराने जीडीपी अनुमान के बाद में हुए पुनर्गणना और आगे के संशोधन का परिणाम है, लेकिन इतना बड़ा संशोधन निश्चित रूप से पारदर्शिता मांगता है। और यह कहना कि बेस ईयर बदल गया, इसलिए 86.05 लाख करोड़ घटकर 80 लाख करोड़ हो गया अधूरा स्पष्टीकरण होगा। नई 2022-23 जीडीपी सीरीज में पुराने अनुमानों को अद्यतन डाटा सोर्स, उन्नत मैथोडोलॉजी, संशोधित कवरेज और अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर पुनर्गणित किया गया। इसके बाद उपलब्ध हुए नए आईआईपी और सीपीआई सूचकांक को भी जीडीपी संकलन में शामिल किया गया। नई जीडीपी सीरीज, बेहतर और अद्यतन डाटा सोर्स, कवरेज तथा उन्नत मैथोडोलॉजी में सुधार और बाद में उपलब्ध नए संकेतकों के आधार पर पुराने जीडीपी अनुमानों को दोबारा गणना किया गया, जिसके कारण पुराने वर्तमान मूल्य अनुमानों में भी बदलाव आया।

आमजन के मन में साधारण-सा सवाल होगा कि वर्तमान मूल्य जीडीपी तो उस समय की कीमतों पर होती है, फिर वह बदल कैसे गई? यही सबसे स्वाभाविक सवाल है। यदि पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2025-26 में वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें वही थीं, तो आज उनके वर्तमान मूल्य में बदलाव कैसे आ सकता है? इसका कारण यह है कि वर्तमान मूल्य जीडीपी भी देश की प्रत्येक आर्थिक गतिविधि का सीधे-सीधे वास्तविक समय में जोड़ा गया अंतिम बिल नहीं है। यह भी राष्ट्रीय लेखांकन की विभिन्न अनुमान विधि और डाटा सोर्स से तैयार किया गया अनुमान है। यदि किसी सेक्टर का कवरेज बदलता है, सोर्स डाटा बेहतर होता है, क्लासीफिकेशन बदलता है, अनुमान विधि सुधरता है या किसी कम्पोनेंट के लिए पहले की तुलना में बेहतर जानकारी उपलब्ध होती है, तो उसी पुराने समय के वर्तमान मूल्य अनुमान को भी संशोधित किया जा सकता है। इसलिए ?86.05 लाख करोड़ का पुराना आंकड़ा और 80.00 लाख करोड़ का नया आंकड़ा दोनों अपने-अपने समय में उपलब्ध जानकारी और लागू सांख्यिकीय फ्रेमवर्क पर आधारित अनुमान हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज का 88.27 लाख करोड़ अंतिम आंकड़ा नहीं है, वह भी एक अनुमान है। आगे अधिक विस्तृत डाटा उपलब्ध होने पर इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अभी जारी 7.8 प्रतिशत को इस्तेमाल ही न किया जाए। अर्थव्यवस्था के हर समय के निर्णय के लिए उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम आधिकारिक अनुमान का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही रास्ता है एक ही जीडीपी सीरीज, एक ही विधि, एक ही प्राइस कांसेप्ट और एक ही तुलनीय आधार पर तुलना। इस कसौटी पर पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2026-27 की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत ही वर्तमान आधिकारिक और तुलनीय आंकड़ा है।

वीबी-जी राम जी क्रियान्विति में राजस्थान का श्रेष्ठ प्रदर्शन

18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार

कार्यालय संवाददाता की रिपोर्ट

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना के सफल क्रियान्वयन से महिलाओं, वंचितों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली वीबी जी राम जी की पहल की है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार की मजबूत गारंटी और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन रही है। इस योजना से रोजगार के साथ-साथ जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसमें सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है।

इस वर्ष (2026-27) योजना के अंतर्गत अब तक राजस्थान में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी राष्ट्रीय औसत से 10.44 प्रतिशत अंक अधिक रही है। राज्य में कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 62.25 प्रतिशत है। यह ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों में उनकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान में योजना के तहत अब तक 18.86 लाख परिवारों और 21.66 लाख व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया है। राज्य में प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन है। इस तरह राजस्थान में औसतन 4.27 दिन अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

42 हजार 557 परिसंपत्तियों का निर्माण



योजना के तहत राजस्थान में 42 हजार 557 परिसंपत्तियों का निर्माण हो चुका है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा रही है। कृषि एवं इससे संबद्ध गतिविधियों पर कुल व्यय का 35.88 प्रतिशत और मिशन जल संरक्षण ब्लॉक पर 73.17 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार गांव-ढाणी में जल जैसी बुनियादी सुविधा पर केन्द्रित होकर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाते हुए इस योजना के तहत वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 20.43 और अनुसूचित जनजाति वर्ग की 23.34 प्रतिशत सहित कुल 44 प्रतिशत सक्रिय हिस्सेदारी से यह योजना अन्त्योदय के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी हिस्सेदारी क्रमशः 18 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस प्रकार दोनों वर्गों की उत्साहजनक भागीदारी में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे है। योजना के तहत राजस्थान में 97.04 प्रतिशत भुगतान 15 दिनों के भीतर जनरेट किए गए, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 82.46 प्रतिशत है। इस प्रकार राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 14.58 प्रतिशत अंक आगे है। राज्य में कुल व्यय का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 99.97 प्रतिशत है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कार्यशाला

डिजिटल गवर्नेंस में साइबर सुरक्षा एवं नागरिकों के डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करें - वी श्रीनिवासन, मुख्य सचिव

जयपुर।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा), जयपुर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने नॉलेज पार्टनर के रूप में सहभागिता की। कार्यशाला में राज्य के सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला के प्रारंभ में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मुख्य वक्तव्य दिया। इस दौरान एचसीएम रीपा की महानिदेशक श्रेया गुहा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सचिव रवि कुमार सुरपुर भी उपस्थित रहे।



साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण अनिवार्य : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए सेवाओं की डिजिटल माध्यम से प्रदायगी आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के प्रभावी विस्तार के लिए नागरिकों के अनुकूल डेटा संरक्षण व्यवस्था विकसित करने के साथ ही उनके व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता के संबंध में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आमजन का विश्वास मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 जैसे कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस प्रकार की कार्यशालाएं महत्वपूर्ण हैं। इससे अधिनियम की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस विषय से जुड़े विभिन्न न्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध नागरिकों के व्यापक व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने नागरिकों एवं सरकारी कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तथा सरकारी डेटा सेंटर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स पर साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपादेयता के आधार पर डेटा का निर्धारित अवधि तक ही संरक्षण एवं समय पर विलोपन, समय-समय पर पासवर्ड बदलने, डेटा गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

कार्यशाला का संचालन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नीतीश कालरा ने किया। कार्यशाला में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के विभिन्न प्रावधानों, उसकी प्रासंगिकता एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित, पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप डेटा का उपयोग किस प्रकार सुशासन, बेहतर प्रशासनिक सेवाओं एवं नागरिकों के हितों को सुनिश्चित करने में किया जा सकता है। साथ ही, व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। अंत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सचिव ने संक्षिप्त उद्बोधन के माध्यम से सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

यह देश!

यह देश किसी के पापा की
जागीर नहीं है बाबू!
ये छुटभैये भारत की
तकदीर नहीं हैं बाबू!!
देश हमारा बनिये की दूकान नहीं है
ज़िंदा इन्सानों का घर है मरघट या श्मशान नहीं है
ये जो सड़कों पर उतरे हैं
भारत के योद्धा हैं
इनकी सूरत पर मत जाओ
ये फकीर नहीं हैं बाबू
यह देश तुम्हारे पापा की
जागीर नहीं है बाबू!
तुम चोरों को संत कहोगे
हत्यारों को महंत कहोगे
डाकू बैठाओगे सिर पर
लोकतंत्र का अंत करोगे
बिरसा मुंडा के तूणीर में
तीर अभी है बाबू
यह देश किसी के पापा की
जागीर नहीं है बाबू
भगतसिंह आजाद का दर है
राम और अशफाक का घर है
अभी हमारे धड़ पर सर है
प्राण लुटाने का अवसर हैं
हमको रोक सके ऐसी
ज़ंजीर नहीं है बाबू
ये छुटभैये भारत की
तकदीर नहीं हैं बाबू
बड़े शूरमा चले गए हैं
हम अपनों से छले गए हैं
अपनी राख से उठने वाले
तूफानों में पले हुए हैं
जुल्म तुम्हारा चार दिनों का
जिसकी दवा नहीं हो ऐसी पीर नहीं है बाबू!
यह देश तुम्हारे अब्बा की
जागीर नहीं है बाबू!

-हूबनाथ पांडेय



हर व्यक्ति की समस्या का करें समाधान, जन सुनवाई को बनाएं प्रभावी माध्यम- - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में वास्तविक सफलता आम नागरिक के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होती है। हमेशा आमजन की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा प्रत्येक निर्णय लिया जाना चाहिए। अधिकारी अपने पद को अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवा के उत्तरदायित्व के रूप में समझें। उन्होंने कहा कि वे अपने संघर्ष और अतीत को याद रखें एवं इससे प्रेरणा लेकर आमजन के हित में कार्य करें तथा अपने उद्देश्य की दिशा कभी न बदलें, क्योंकि जीवन की असली परीक्षा तो जिम्मेदारी के पद पर बैठने के बाद शुरू होगी।

मुख्यमंत्री एचसीएम रीपा (ओटीएस) के बी एस मेहता सभागार में राज्य सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष आरएएस भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी हर व्यक्ति और पूरे राजस्थान को अपना परिवार समझें तथा पूर्ण संवेदना के साथ आमजन से जुड़कर उनकी समस्या का समाधान करें।

जनविश्वास सबसे बड़ी पूंजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद के साथ आता है। ऐसे में अधिकारियों का व्यवहार, कार्यशैली और निर्णय उस व्यक्ति का प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसेवा में अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र और जनता का विश्वास होता है। इसलिए ईमानदारी और निष्पक्षता को अपने कार्य का आधार बनाएं। उन्होंने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित करें, जिसमें लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ें और प्रत्येक व्यक्ति की बात सम्मानपूर्वक सुनी जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में जाकर लोगों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और स्थानीय परिस्थितियों को समझें। जनसुनवाई को केवल औपचारिक गतिविधि तक सीमित न रखते हुए समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतियां और योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और उसके जीवन में वास्तविक सुधार दिखाई दे। इसके लिए अधिकारियों को योजनाओं की पात्रता, प्रक्रियाओं और समयसीमा की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं निर्धारित करने, स्पष्ट लक्ष्य तय करने तथा नियमित रूप से उनकी प्रगति की समीक्षा करने पर बल दिया।

तकनीक का उपयोग करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएं, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) शासन एवं प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। युवा अधिकारी अपनी तकनीकी समझ का उपयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय की बचत



करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल तकनीक का उपयोग नहीं कर पाने के कारण कोई व्यक्ति सरकारी सेवा के लाभ से वंचित न रह जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाओं से भरा हुआ है। उसे अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। राज्य सरकार युवाओं की क्षमताओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य में 1 लाख 93 हजार पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वहीं, वर्ष 2026 में सवा लाख पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इसी राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान-2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खनन, उद्योग, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजारों से जोड़ने, ऐतिहासिक धरोहर एवं समृद्ध लोकसंस्कृति के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देने तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना भी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रशिक्षु अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दिशा में नीतियों को धरातल पर लागू करने, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान में उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही, उन्हें विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए दूरदृष्टि के साथ प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि प्रशासन में ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता ही जनविश्वास की सबसे मजबूत नींव हैं। वे अच्छे विचारों को व्यवहार में लाकर सभी को साथ लेकर साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सबसे बड़ी उपलब्धि वह विश्वास होगा, जो आम नागरिक उनके प्रति व्यक्त करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान के विकास का रोड मैप बनाया जिसके तहत सबसे पहले जल उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए गए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को 4 जल समझौतों की सौगात मिली, जिसमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौता शामिल है। राज्य सरकार इनसे जुड़े विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देवास, माही और ब्राह्मणी जैसी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर प्रदेश बना है। 27 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है और वर्ष 2027 तक सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। इनमें से लगभग 9 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भी शुरू हो चुकी है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण से प्रदेश में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाबदेही, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता से सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्र प्रथम की भावना के जरिए राष्ट्रसेवा का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने 181 हेल्पलाइन का नियमित दौरा कर हम सभी के लिए नागरिक-केंद्रित सुशासन का प्रेरणादायक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु अधिकारियों को सुशासन, जनसेवा और प्रशासनिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है।

इस अवसर पर महानिदेशक एचसीएम रीपा श्रेया गुहा सहित अन्य अधिकारीगण एवं राज्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, वीसी के माध्यम से उदयपुर से भी प्रशिक्षु अधिकारी इस संवाद कार्यक्रम में जुड़े।

सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए-डीआर 3% बढ़ाया

जयपुर

केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत (डीआर) तीन फीसदी बढ़ा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद डीए बढ़ाने के आदेश हो गए हैं। इसके साथ ही दिवाली पर 6 लाख कर्मचारियों को 7 हजार तक बोनस देने का भी आदेश जारी हो गए। राजस्थान में करीब 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। राज्य कर्मचारियों के साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के

अब 63% हुआ, दिवाली पर 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। इससे सरकार पर करीब 820 करोड़ का आर्थिक भार आएगा।

अब तक राजस्थान में कर्मचारियों को 60 फीसदी डीए और पेंशनर्स को 60 फीसदी महंगाई राहत (डीआर) मिल रहा था। अब बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 63 फीसदी डीए और पेंशनर्स को 63 फीसदी डीआर मिलेगा।

राज्य सरकार ने इसी साल अप्रैल में कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए दो फीसदी बढ़ाया था। अप्रैल में डीए 58% से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया था।

राजस्थान में पिछले लंबे समय से केंद्र की घोषणा के बाद कुछ समय बाद ही राज्य सरकार भी डीए बढ़ाती रही है। अप्रैल में केंद्र सरकार के डीए बढ़ाने की घोषणा के पांचवें दिन राजस्थान सरकार ने भी DA बढ़ा दिया था।

500 से लेकर 4500 रुपए तक होगा फायदा

डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को वेतनमान के हिसाब से अलग-अलग फायदा होगा। एल-1 से लेकर एल-24 तक वेतनमान के हिसाब से अलग-अलग राशि बनती है। डीए बढ़ने से 500 से लेकर 4500 रुपए तक प्रति माह वेतन में बढ़ोतरी होगी।

डीए बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में 820 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बढ़ा हुआ डीए जुलाई से लागू होगा। जुलाई से अक्टूबर तक के DA का बकाया कर्मचारियों के GPF (सामान्य भविष्य निधि) खातों में जमा किया जाएगा। बढ़ा हुआ D कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा। पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से बढ़ा हुआ DR नकद में दिया जाएगा।

6 लाख कर्मचारियों को अधिकतम 7000 रुपए तक एडहॉक बोनस मिलेगा। बोनस का लाभ पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 तक के कर्मचारियों को ही मिलता है।

जेन-जी अब वैश्विक आंदोलन बन चुके हैं..हल्के में मत आंकिए!

एक ही हफ्ते में तीन देशों में सत्ता की विदाई..कहानी एक!

वैश्विक राजनीतिक हालातों पर 'राजनीतिक संवाददाता' की व्याख्या

विश्व भर में युवाओं का असंतोष जेन-जी के आंदोलनों के माध्यम से मुखर हो रहा है..कहीं चरम परिणति याने सत्ता परिवर्तन की कथा लिख चुका है..तो कहीं उस रास्ते पर चल रहा है। अभी हाल में तीन देशों में सत्ता परिवर्तन के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही युवा पीढ़ी है। सर्बिया में 14 साल से सत्ता में बैठे एलेक्जेंडर वुचिच हार चुके हैं, जिन्होंने मीडिया पर कब्जा कर रखा था। जजों से वो फैसले दिलाए गए जो सरकार के पक्ष में होते थे। आंदोलन करने वालों पर लाठियां चलवा कर या उन्हें अपनी पार्टी के समर्थक गुंडों से पिटवा कर जेल में डालते रहे।

और हराया किसने है? किसी पार्टी ने नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही मोर्चा खोला..खेल पूरा किया! दो साल पहले रेलवे स्टेशन की छत गिरी, 16 लोग मरे। छात्रों ने कहा था ये हादसा नहीं, भ्रष्टाचार है। वे सड़कों पर उतरे सरकार ने आंदोलन कुचलने का प्रयास किया,लेकिन आंदोलन बढता ही गया। फिर छात्रों ने पार्टी बनाई और चुनावो में अपने प्रत्याशी उतार दिए। 25 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए और छात्रों की पार्टी ने 140 सीटें जीत कर प्रचंड बहुमत से सत्ता हांसिल कर ली !

और वुचिच ने टीवी पर आकर कहा - ये क्रांति यूरोप और अमेरिकी जैसी विदेशी ताकतों ने कराई है।

ब्राजील में पिता जैर बोल्सनारो ने 2022 में यही किया था, बेटे ने 2026 में दोहराया। बोल्सनारो लूला से हारे..उन्होंने धांधली का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट मांगा..लेकिन चकमा देकर अगले दिन बीवी-बच्चों के देश छोड़कर अमेरिका भाग गए! अमेरिका पहुंच जहाज से उतरते ही बयान आया, मैं भागा नहीं, मैं ही असली राष्ट्रपति हूं, अमेरिका से विपक्ष चलाऊंगा।

और अब तीसरे देश इजराइल में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा युद्ध, सबसे ज्यादा केस फिर भी नेतन्याहू अभी तक टिके हैं। 27 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 53 सीटें मिलीं, बहुमत के लिए 61 चाहिए। विरोधी ब्लॉक के पास 48 हैं। अब किंगमेकर कौन? 19 सीटों वाली अरब पार्टियां, जिनके साथ आज तक किसी यहूदी पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। यानी नेत्यनाहू चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने अरब पार्टियों पर वोट चोरी का आरोप लगाया!

तो 3 देश, 3 महाद्वीप, एक पैटर्न।

इसे दक्षिणपंथ बनाम वामपंथ ही मत समझिए..ये सत्ता के विरुद्ध सड़क की लड़ाई है! पूरी दुनिया में जेन-जी अब वोट नहीं, हिसाब मांग रहा है। आप जब इसे पढ़ रहे हैं तब आपको किसी कहानी किस्से की तरह लग रहा होगा। सर्बिया में छात्र, ब्राजील में बाप-बेटा, और अब इजराइल में नेत्यनाहू की हार..जैसे तीनों जगह एक ही हफ्ते में राजनीति के प्रहसनों को फाइनल चल रहा है। एक हफ्ते में 3 देशों के ऐसे प्रधानमंत्री कुर्सी से उतार दिए गये हैं, जिन्हें लगता था कि वो देश के लोगों को डरा धमकाकर मीडिया पर..अदालतों पर.. कब्जा करके सतत सत्ता सुंदरी का स्वयंवर किए बैठे हैं! उनके समर्थकों को भी लगता था कि उनकी पार्टी कभी चुनाव हारेगी ही नही ! लेकिन जब वक्त बदलता है और सत्ता हाथ से जाती है तो देश छोड़कर भागना पड़ता है, इससे दूसरों को सीख लेना चाहिए..ऐसे बीज नही बोने चाहिएं कि अगर फसल काटने की बारी आए..तो फसल काटना मुश्किल हो जाए! याद रखिए यह कहानी तो सिर्फ एक हफ्ते की है..इससे पहले नेपाल, बांग्लादेश जैसे किस्सों को तो हम बाद में समझेंगे..गुनेंगे!

अब बात भारत जेन-जी आंदोलनों की..

भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां की 50त्न से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है. हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में एक संरचनात्मक बदलाव देखने को मिला है, यह बदलाव है जेनरेशन जी और स्वतंत्र, गैर-दलीय युवा आंदोलनों का उभार। पारंपरिक छात्र राजनीति (जो अमूमन मुख्यधारा की पार्टियों की छात्र इकाइयों जैसे एनएसयूआई, विद्यार्थी परिषद या वामपंथी संगठनों तक सीमित रहती थी) से इतर, यह नया युवा वर्ग किसी पार्टी-हाईकमान या पारंपरिक विचारधारा के बंधनों से मुक्त होकर सीधे सरोकारों पर बात कर रहा है।



पारंपारिक राजनीतिक दलों के समक्ष खड़ी चुनौतियां

एक तुलनात्मक और व्यवस्थित विश्लेषण

चुनौती का आयाम	पारंपरिक दलों की कार्यशैली	जेन-ज़ी/स्वतंत्र आंदोलनों की अपेक्षा
संगठनात्मक ढांचा	पदानुक्रमित (Hierarchical), हाईकमान केंद्रित, वंशवादी/सीनियरिटी आधारित।	क्षैतिज (Horizontal), खुला, मेरिट-आधारित और तुरंत संवाद चाहने वाला।
राजनीतिक भाषा	भावनात्मक, अतीत-केंद्रित, पहचान की राजनीति (धर्म/जाति)।	डेटा-आधारित, रोजगारोन्मुख, तार्किक और भविष्य-केंद्रित।
सहमति / असहमति	कैडर से अंधी निष्ठा की मांग, असहमत आवाजों को विरोधी खेमे का मानना।	सत्ता या पार्टी से सवाल पूछने को नागरिक का बुनियादी अधिकार मानना।
प्रतिनिधित्व	युवा मोर्चा केवल 'भीड़ जुटाने' और 'पोस्टर लगाने' तक सीमित।	वास्तविक नीति-निर्माण और टिकट वितरण में सार्थक भागीदारी।

सामूहिक नेतृत्व और विकेंद्रीकृत ढांचा

पारंपरिक आंदोलनों के विपरीत, ये आंदोलन किसी एक करिश्माई नेता के इर्द-गिर्द केंद्रित नहीं होते। इनका नेतृत्व नेटवर्क आधारित और विकेंद्रीकृत होता है, जिससे सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बातचीत या कार्रवाई हेतु किसी एक केंद्र को निशाना बनाना कठिन हो जाता है। सामूहिक नेतृत्व के बीच लगातार स्थापित होने की स्वाभाविक आकांक्षा जल्दबाजी में समझौतों से तो बचाती ही है, लंबे समय में नेतृत्व क्षमता के विकास को भी जमीनी पकड़ देती है। यही वह जगह है जहां से अपार संभावनाओं के साथ निर्णय क्षमता का भी निर्माण होता है।

सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट, यूट्यूब) इनके लिए केवल प्रचार का साधन नहीं, बल्कि विचार-विमर्श और मोबिलाइजेशन का मुख्य मंच है। मीम्स, रील्स, पॉप-कल्चर प्रतीकों और तीखे व्यंग्य का उपयोग कर जटिल राजनीतिक और प्रशासनिक नाकामियों को तुरंत आम समझ में बदल दिया जाता है। विचारधारा से अधिक सरोकार याने मुद्दों पर केंद्रित आन्दोलनों का तोड़ सत्ता पक्ष के पास भी तुरंत उपलब्ध नहीं होता। युवा वर्ग राइट बनाम लेफ्ट के पुराने खांचों से बाहर निकलकर व्यावहारिक मुद्दों जैसे भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, पारदर्शी शासन, जलवायु न्याय, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक अनिश्चितता पर केंद्रित है।

अधिकार की चेतना

यह पीढ़ी सरकार को माई-बाप के बजाय एक सेवा-प्रदाता मानती है। नीतिगत विफलताओं पर सवाल पूछना उनके लिए कोई बगावत नहीं, बल्कि नागरिक के रूप में उनकी कानूनी व लोकतांत्रिक हकदारी है। यह पीढ़ी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को एक समान प्राथमिकता से उठाने की अभ्यस्त है, यह खूबी उन्हें आम नागरिकों के मध्य स्वीकार्य तथा समझदार मानने को बाध्य करती है।

भारतीय लोकतंत्र में भूमिका

स्वतंत्र युवा समूह सीधे तौर पर संस्थागत विचलनों (जैसे परीक्षा प्राधिकरण, चुनाव आयोग या नियामक संस्थाएं) पर सवाल उठाते हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर तुरंत जन-दबाव बनता है। अब तक मुख्यधारा का मीडिया और बड़ी पार्टियां तय करती थीं कि देश में किस विषय पर बहस होगी। स्वतंत्र युवा आंदोलन डिजिटल ट्रेंड्स और स्ट्रीट एक्टिविज्म के जरिए उन मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने में सक्षम हैं जिन्हें पारंपरिक मीडिया दरकिनार कर देता था। दबाव समूह के रूप में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो चली है, चाहे वह भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार की मांग हो या प्रशासनिक जवाबदेही, इन आंदोलनों की गतिशीलता सरकारों को त्वरित जांच कमेटियों या नीतिगत बदलावों के लिए विवश करती है।

पारंपरिक राजनीतिक दलों की चुनौतियां

पारंपरिक दलों की कार्यशैली में जेन-जी या स्वतंत्र आंदोलनों की अपेक्षा संगठनात्मक ढांचा अधिक प्रभावी होता है। इन दलों में पदों की वरिष्ठता होती है..लगभग सभी दलों में हाईकमान केंद्रित निर्णयात्मक ढांचा कार्य करता है। आजकल तो अधिकांश दलों का परिवार आधारित होना भी अलग विषय हो चुका है। इन दलों में अपनी राजनीति की जातिगत या धर्मगत पहचान हावी होना भी कोई अजूबा नहीं है। कैडर आधारित दलों में भी अंधी निष्ठा की बीमारी घर कर चुकी है। कहने को लोकतांत्रिक दल हैं, लेकिन विरोध की आवाज को विरोधी खेमे का माना जाना बेहद सामान्य है। योग्यता आधारित दलों का अब कोई नामलेवा नहीं बचा है। युवा प्रतिनिधित्व के आम पर युवा मोर्चा केवल भीड़ जुटाने और पोस्टर लगाने तक सीमित रह गए हैं। वास्तविक नीति-निर्माण और टिकट वितरण में सार्थक भागीदारी इन दलों में युवाओं को नहीं मिल रही।

इन सबके विपरीत दुनिया भर में हो रहे आन्दोलनों से साफ दिखेगा कि मेरिट आधारित और तुरंत संवाद चाहने वाली राजनीतिक व्यवस्था अपने आप आकार ले रही है। राजनीतिक भाषा भावनात्मक न होकर तथ्य आधारित होने लगी है, अतीत केंद्रित पहचान की राजनीति का स्थान डेटा आधारित, रोजगारोन्मुख, तार्किक और भविष्य केंद्रित राजनीति इन आन्दोलनों के कारण आकार ग्रहण कर रही है। सत्ता या पार्टी से सवाल पूछने को नागरिक का बुनियादी अधिकार अब फिर से आकार ले रहा है। राजनीतिक दलों में युवा प्रतिनिधित्व के नाम पर युवा मोर्चा केवल भीड़ जुटाने और पोस्टर लगाने तक सीमित रहते आए हैं। वहां वास्तविक नीति-निर्माण और टिकट वितरण में सार्थक भागीदारी का नितांत अभाव रहा है। कुल मिलाकर पारंपरिक दलों के वादों और जमीनी हकीकत के अंतर से युवाओं का राजनीतिक तंत्र से भरोसा कमजोर हुआ है। वे किसी एक दल की विफलता को दूसरे दल की योग्यता नहीं मानते।

जब पार्टियां ऐसे आंदोलनों को हाईजैक करने या उनके मंच पर अपना झंडा लगाने की कोशिश करती हैं, तो युवा तुरंत उनसे दूरी बना लेते हैं। टूलकिट या साजिश का नैरेटिव उलटे पड़ने लगे हैं। पारंपरिक सत्ता-संरचनाएं अक्सर स्वतंत्र युवा विरोध को बाहरी उकसावा या विपक्षी षड्यंत्र करार देती हैं। यह दृष्टिकोण युवाओं के भीतर आक्रोश को और गहरा करता है, क्योंकि यह उनकी वास्तविक परेशानियों को खारिज करता दिखता है। यद्यपि स्वतंत्र युवा आंदोलन राजनीतिक तंत्र को झकझोरने में सफल रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ संरचनात्मक सीमाएं भी हैं। डिजिटल सक्रियता और तात्कालिक विरोध प्रदर्शन जल्दी शुरू तो होते हैं, मगर ठोस सांगठनिक ढांचे के अभाव में वे जल्दी बिखर भी सकते हैं। सड़कों की ऊर्जा को मतदान केंद्र तक ले जाना और नीतिगत सुधारों को संस्थागत कानूनी रूप देना इन आंदोलनों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक विनोद जोशी* द्वारा राज ब्लॉक बी 81 करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया 22 गोदाम जयपुर से मुद्रित तथा एल/7, केड़िया अमारा, टेवलर स्कूल के पास, महाराणा प्रताप मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर - 302041 राजस्थान से प्रकाशित। *समाचार चयन के लिए पीआरवी एक्ट के तहत जिम्मेदार, मो. 94140 46542